फोनः-4103333, 2362400 फैक्सः-0141-2373513 वर्षः 73 संख्याः 185 प्रभात जयपुर, रविवार 5 फरवरी, 2023 डाक पं.सं. जयपुर सिटी/001/2021-23 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

ARBiT

जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

Suchitra Sen- A Legend Beyond Death

She did not need to show skin, or flash a thigh or reveal a cleavage to exude sex appeal: Uttam Kumar

Trends&Gadgets: Tips and Tricks

Tried&Tasted: Beyond Dreamy

There's a way to eat Nutella for breakfast, lunch and dinner

लगभग एक दशक तक ब्रिटिश म्यूज़ियम के अधिकारी, ग्रीस को एल्गिन मार्बल्स लौटाने के बारे में बात तक नहीं करते थे, लेकिन अब ग्रीक हैरिटेज अधिकारियों के साथ इस बारे में बात करने को राजी हो गए हैं। संभावना है कि, अब शायद ये कलाकृतियाँ ग्रीस को लौटा दी जाएं। एल्गिन मार्बल्स या पार्थेनॉन मार्बल्स, मूर्तियों और फ्रीज (चित्र वल्लरी) का एक संग्रह हैं, जो मूलतः ईसापूर्व 5 वीं सदी में ग्रीस के अथीनियन एक्रोपोलिस पर पार्थेनॉन टैम्पल में था। देवी एथीना का यह मंदिर यूनानी कला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। एल्गिन मार्बल्स को न केवल लोकतंत्र का, बल्कि पश्चिमी सभ्यता के जन्म का प्रतीक भी माना जाता है। उन्नीसवीं सदी के आरंभ में ब्रिटिश अभिजात्य वर्ग के टॉमस ब्रूस, एल्गिन के सातवें अर्ल, एक सैनिक, राजनीतिज्ञ, व तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में ब्रिटेन के राजदूत भी थे, जिसका उस समय यूनान पर राज था। एतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार टॉमस ब्रूस ने एथैन्स के पार्थेनॉन मंदिर से विवादास्पद रुप से ये प्राचीन मार्बल मूर्तियां हथिया ली थीं। उस समय लॉर्ड बायरन ने इस कदम को ''कल्चरल वैंडलिज़्म'' (सांस्कृतिक गुंडागर्दी) की संज्ञा दी थी। हालांकि 1810 में ब्रिटिश संसदीय कमेटी ने एल्गिन का समर्थन किया और फिर ब्रिटिश सरकार ने 1816 में 35,000 पाउण्ड देकर एल्गिन मार्बल्स खरीद लिए, तब से ये ब्रिटिश म्यूज़ियम में प्रदर्शित हैं। अब संभवतया वे एथैन्स को लौटाए जा सकते हैं।

वित्त मंत्री ने अडानी प्रकरण में सरकार की छवि बचाने की पूरी कोशिश की

निर्मला सीतारमन ने कहा, सरकार रैग्युलेटर्स, आर.बी.आई., सेबी आदि को अडानी प्रकरण में पूरा काम निष्पक्षता से करने की स्वतंत्रता देगी

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। छवि को हो चुके नुकसान को रोकने (इमेज डैमेज कंट्रोल) की कवायद में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हो गईं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक अडानी ग्रुप के खिलाफ लगे फ्रॉड के आरोपों का प्रश्न है, सरकार नियामकों (रेग्यूलेटर्स) को अपना काम करने देगी। ज्ञातव्य है कि अडानी ग्रुप के खुलासे के बाद स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयरों को औने-पौने दामों में बेचा जाना शुरु हो गया, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ।

सीतारमन ने ''न्यूज़ ब्रीफिंग'' के दौरान कहा, ''रेग्यूलेटर अपना काम करेंगे। आपने इस बिन्दु पर कल रिज़र्व बैंक का बयान पढ़ा होगा और इससे भी पहले, बैंक तथा एल.आई.सी. स्वयं आगे आकर यह कह चुके हैं कि उनका ''लेवल ऑफ एक्सपोज़र'' क्या है। इस प्रकार रेग्यूलेटर अपना काम करेंगे।'' ऐसा प्रतीत होता है कि अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और प्रधानमंत्री

(शेष पृष्ठ 7 पर)

- वित्त मंत्री के अनुसार रिज़र्व बैंक (आर.बी.आई.) तो इस प्रकरण के बारे में अपनी टिप्पणी दे ही चुका है।
- साथ ही लाइफ इन्शोरैंस कॉरपोरेशन व अन्य बैंक भी बता चुके हैं, उनका कितना ''एक्सपोज़र'' है अडानी ग्रुप में।
- सोशल मीडिया पर भी भारी प्रचार हो रहा है कि, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का मकसद केवल मोदी सरकार व भारत की सार्वभौमिकता के खिलाफ साजिश रचना है।
- वित्त मंत्री ने आक्रामक रूख अपनाते हुए, यह भी कहा कि, अडानी द्वारा एफ.पी.ओ. वापस लेने को कोई बड़ी बात नहीं माना है, क्योंकि कई बार पहले भी एफ.पी.ओ. ''कैंसल'' हुए हैं भारत में, पर इनसे क्या कभी किसी की छवि को भारी क्षति पहुंची।
- आर.बी.आई. ने इसमें आगे जोड़ा कि, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, लिक्विडिटी तथा प्रॉफिटबिलिटी की दृष्टि से अडानी ग्रुप काफी ''स्वस्थ'' है।
- दूसरी ओर यह भी खबर है कि, हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप की सात कम्पनियों की मार्केट वैल्यू में सौ बिलियन डॉलर की कमी हुई है।

पाकिस्तान के प्र.मंत्री शहबाज़ शरीफ के आगे कुआं और पीछे खाई है

उनके लिये आई.एम.एफ. से ऋण लेना नितान्त आवश्यक है, नहीं तो देश की ''इकॉनमी'' व व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। पाकिस्तान में अब जीवन दु:ख और आर्थिक उदासी भरा है। अधिकांश आबादी हाल ही आयी बाढ़ से उत्पन्न परेशानियों में कैसे भी मदद पाना चाह रही है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल है और वित्तीय मदद मिलना भी मुश्किल है।

पाकिस्तान की सरकार के लिए यह समय खासतौर पर तब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जनता पद और भार डालने का नहीं है, क्योंकि जनता की तो पहले ही कमर टूट चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री शेहबाज़ शरीफ को इन्टरनैशनल मॉनिटरी फण्ड (आई.एम.एफ.) से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा।

शेरीफ पकड़ो या छोड़ो जैसी स्थिति वाले एक दोराहे पर खड़े हैं। आई.एम.एफ. इस गरीब देश को उसकी बुरी आर्थिक स्थिति से निकालने के लिए ''बेल आउट'' करने का इच्छुक है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि उसकी शर्तें कठोर हैं। आई.एम.एफ. ने इस बात पर जोर दिया है कि पाकिस्तान को टैक्स वृद्धि करनी होगी और जनता को दी जा रही सब्सिडीज़ को खत्म करना होगा, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके, अन्यथा उसे बेल आउट पैकेज

- पर, कमर तोड़ महंगाई, बाढ़ के कारण अपने घुटनों पर आई पाकिस्तान की जनता, और कीमतें बढ़ना बर्दाश्त नहीं कर पायेगी।
- वहीं, आई.एम.एफ. की ऋण देने की शर्तों में सबसे अहम् है टैक्स बढ़ाना व सब्सिडी खत्म करना, जिससे इकॉनमी शायद ही अपने पैरों पर खड़ी हो सके।
- पाकिस्तान में अक्टूबर में चुनाव हैं, अतः ये सख्त शर्तें कैसे लागू की जा सकती हैं?
- यह बात पाक प्र.मंत्री अच्छी तरह समझ रहे हैं, पर अगर आई.एम.एफ. का ऋण नहीं मिला तो, वैसे अपने आप मरण होगा।
- इस दुविधा में पाक प्र.मंत्री कोई चमत्कारिक विकल्प ढूंढ रहे हैं, पर कोई जादूगरी कामयाब होती नज़र नहीं आ रही है।

उपलब्ध नहीं करवाया जाएगा। शरीफ टैक्स बढ़ाए जाने की संभावनाओं को लेकर परेशान हैं। उन्हें इसी वर्ष के अक्टूबर माह में आम चुनावों का सामना करना है और आई.एम.एफ. की शर्तें स्वीकार करने का उनके लिए मतलब होगा अपने देश की जनता से पूर्णतया विमुख होना और वह इस बात से वाकिफ हैं। फिर भी, उन्हें लगता है कि आई.एम.एफ. द्वारा तय की गई कठोर शर्तों को मानने का प्रयास कर रही है, इसलिए उन्होंने अपने देशवासियों को चेताया है कि वे अब आगे और कठिन समय के लिए स्वयं को तैयार रखें।

ए.एफ.सी. की एक रिपोर्ट के अनुसार शरीफ ने शुक्रवार को कहा कि आई.एम.एफ. ने पाकिस्तान के समक्ष ''बेल आउट'' की जो शर्तें रखी हैं वे कल्पना से परे हैं।''

शेहबाज़ शरीफ ने मीडिया को बताया कि ''मैं इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ही कहूंगा कि हमारी आर्थिक चुनौती अकल्पनीय है। आई.एम.एफ. के साथ हमें जिन शर्तों पर सहमत होना है, वे कल्पना से परे हैं।'' आई.एम.एफ. का एक प्रतिनिधिमण्डल गत मंगलवार को इस्लामाबाद आया और उसने अति महत्वपूर्ण बेल आउट पैकेज पर पुनः बातचीत के एक अंतिम प्रयास के रूप में पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों से वार्ता कर देश के फायनैंशियल सिस्टम की समीक्षा की। यह पैकेज पिछले कई महीनों से अटका पड़ा है। चूंकि पाकिस्तान में आगामी अक्टूबर माह में आम चुनाव हैं, इसलिए प्रधानमंत्री शेहबाज़ शरीफ के नेतृत्व

(शेष पृष्ठ 7 पर)

एक झटके में ही गौतम अडानी ने आधी सम्पत्ति गंवाई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। अभी दो सप्ताह भी नहीं हुए जब भारत के अरबपति गौतम अडानी विश्व के चौथे नम्बर के सबसे अमीर थे, उनकी अपनी सम्पत्ति 120 अरब डॉलर थी। यह उद्योगपति बिल गेट्स और वॉरेन बेफट से भी ज्यादा अमीर था।

उसकी कम्पनियों की कीमत 110 अरब डॉलर तक घट गई है और उनकी

- अभी दो सप्ताह पहले तक भारत के अरबपति गौतम अडानी, बिल गेट्स और वॉरैन बफैट से भी ज्यादा अमीर माने जाते थे और विश्व के चौथे नम्बर के सबसे अमीर व्यक्ति थे।

अपनी सम्पत्ति भी आधी ही बची है क्योंकि उन्होंने 61 अरब डॉलर गंवा दिए है। हिंडनबर्ग रिसर्च के बाद निवेशकों ने अपना समर्थन वापस ले लिया है। इस अमेरिकन रिसर्च कम्पनी ने उन्होंने कॉरपोरेट इतिहास की सबसे बड़ी धोखाधड़ी का साजिश रचने वाला बताया। अडानी समूह ने इस रिपोर्ट की निंदा की और इसे निराधार और साजिश

(शेष पृष्ठ 7 पर)

भारतीय सरकार ने आक्रामक रूख अपनाया डॉक्युमैंटरी के बारे में

भारत सरकार विशेष रूप से आहत महसूस कर रही है, ब्रिटेन सरकार के इस रूख से कि, बी.बी.सी.अपना ''कंटैंट'' निर्धारित करने के बारे में पूर्णतया स्वतंत्र है

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। भारत सरकार इंग्लैंड के खिलाफ अब जवाबी अभियान शुरु करेगी क्योंकि इंग्लैंड ने बी.बी.सी. डॉक्यूमैंट्री के टेलीकॉस्ट पर रोक लगाने के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है। ज्ञातव्य है कि इस डॉक्यूमैंट्री में 2002 के गुजरात दंगों, जो नरेन्द्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में उनकी देखरेख में हुये थे, को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बहुत खराब रूप में प्रोजैक्ट किया गया है। भारत में दो हिस्सों में बनी इस डॉक्यूमैंट्री के टेलीकॉस्ट पर पहले ही प्रतिबंध लगा चुका है।

ब्रिटेन सरकार ने अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा है कि ''बी.बी.सी. अपने इस उत्पाद (आउटपुट) के मामले में स्वतंत्र है।'' भारत ने इस स्थिति पर जवाबी हमला करने का निर्णय लिया है। वह इंग्लैंड पर आरोप लगायेगा कि वह खालिस्तानी तत्वों तथा कश्मीर के लिये लड़ रहे पाकिस्तान-समर्थित तत्वों के समर्थकों को आश्रय दे रहा है। ये संदेश आज लंदन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार टिम बैरो के साथ हो रही मीटिंग में उन्हें दे देंगे। भारत और इंग्लैंड इस साल मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप प्रदान करने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत सरकार यह संदेश साफ तौर पर दे देना चाहती है कि अगर इंग्लैंड भारत के साथ व्यापार-व्यवसाय करना चाहता है तो उसे अपनी सोच में बदलाव/संशोधन करने की जरूरत होगी। भारत इस बात को लेकर अशांत है कि इंग्लैंड के विदेश मंत्रालय के मार्गदर्शन में, बी.बी.सी. को इस बात की अनुमति प्रदान कर दी गई कि वह, गुजरात के दंगों के प्रकरण को फिर से खोलने की कोशिश करके, साम्प्रदायिक आधार पर भारतवासियों का ध्रुवीकरण करे, जबकि भारत का सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में नरेन्द्र मोदी को

- भारत सरकार ने ब्रिटेन को याद दिलाया कि, ब्रिटिश सरकार खालिस्तानी आतंकवादियों व पाकिस्तान समर्थित कश्मीरी प्रदर्शन कारियों को ब्रिटेन में पनपने का मौका देती है।
- साथ ही भारत के आर्थिक अपराधियों, जैसे नीरव मोदी, माल्या, संजय भण्डारी, को भी भारत भेजने के बारे में अड़चनें डालती है, हालांकि भारत व इंग्लैण्ड में ''एक्सट्रडिशन'' संधि है।
- भारत के एन.एस.ए. अजीत डोवाल भी लंदन में आज ये मुद्दे उठायेंगे, ब्रिटिश एन.एस.ए. के समक्ष बातचीत के दौरान।

(शेष पृष्ठ 7 पर)

गोवा में हैलिकॉप्टर टूरिज़्म सेवा शुरू

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को गोवा में हैली-टूरिज्म सेवा शुरु कर दी।

इस योजना के तहत, ओल्ड गोवा में दौजी-एला हेलीपेड बनाया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी 'स्वदेश दर्शन स्कीम' के माध्यम से इस प्रोजैक्ट में बहुत बड़ा योगदान दिया है।

गोवा पर्यटन ने इस अवसर पर एक 'कॉल सैन्टर फैसिलिटी भी शुरु की है। यहाँ कार्यरत ऑपरेटर ऐग्ज़ीक्यूटिव चार्टर्स, इन्टरस्टेट ट्रांसफर्स, एयरपोर्ट ट्रांसफर्स तथा कस्टमाइज्ड हेली-टुअर्स की सेवाएं प्रदान करते हैं।

- गोवा के मुख्यमंत्री ने स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत यह सेवा शुरू की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सैन्टर पर्यटन को शीर्ष प्राथमिकता दे रहा है, जैसा कि हाल ही के बजट में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 'अमृत काल' स्कीम के अनुरुप, राज्य सरकार भी हैल्थ तथा वैलनैस टूरिज्म पर विशेष ध्यान दे रही है।

क्या जयपुर भी न्यूयॉर्क की तरह अपनी चिड़ियों की हैल्थ की रक्षा के लिये निर्णय लेगा?

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। मैं होटल ''जयपुर इन'' के तीसरे फ्लोर की बालकनी में खड़ा था। उसके मालिक पुष्पेन्द्र भार्गव ने सांझ के आकाश में चल रही एक काली आकृति की ओर इशारा किया।

उन्होंने बताया कि यह पक्षियों का झुंड है जो रात्रि विश्राम के लिये कहीं रूकने से पहले उड़ रहा है। ये सभी पक्षी ''मैना'' थे जो होटल के सामने स्थित पार्क के बीच मौजूद एक बड़े वृक्ष पर बैठ गए। मैंने काली आकृति को कुछ समय के लिए अलग-अलग समूहों में बंटते देखा और फिर मैं अपने कमरे में चला गया।

कुछ समय बाद मुझे लगा, कि मैं कुछ ऐसा सुन रहा था जैसे कि दूर बह रहे किसी झरने की आवाज़ हो। यह ऐसी ध्वनि थी जो शायद हवा के रूख के साथ कम ज्यादा हो रही थी। जयपुर जैसे व्यस्त शहर के बीच में एक झरना कैसे हो सकता है। मैं कमरे से बाहर आया और यह पता लगाने के लिए बालकनी में आकर बैठ गया कि आखिर आवाज आ कहा से रही है। यह आवाज साफ तौर पर बड़े पेड़ से आ रही थी।

यह बड़ी संख्या में मौजूद चिड़ियाओं का कोलाहल था जो पेड़ पर आकर बैठने के साथ ही चहचहाने लगी थीं। एक तरह से यह अविश्वसनीय था। चिड़ियाओं का इतना बड़ा झुण्ड इतने बड़े शहर के बीचों-बीच अपना

- जाने-माने पत्रकार अंजन रॉय को अपने जयपुर प्रवास के दौरान बनीपार्क में शाम के बाद पक्षियों का कलरव देख कर, खुशी तो जरूर हुई, पर बनीपार्क के सैन्ट्रल पार्क पर लगी भारी व ऊँची निऑन लाइट्स पर प्रश्न उठाये।

अस्तित्व बनाकर कैसे रह सकता है, जहां उन्हें अपना रोजाना का भोजन बमुश्किल ही मिल जाएगा पर अपना दैनिक काम-काज निबटाने की उन्हें शायद ही कोई जगह मिल पाए?

जयपुर इन के मालिक भार्गव ने बनीपार्क सर्किल के एक तरफ एक बड़े खुले स्थान और उसी क्षेत्र में मौजूद अन्य खुली जगहों की ओर इशारा किया। फिर रात हो गई, लेकिन पक्षियों के कलरव का स्वर उतना ही तीव्र था। मैंने आश्चर्य जताया कि हो गया रहा है, पक्षी रात्रि तक अपने समवेत स्वरों के साथ गा रहे हैं।

फिर पता चला कि, बनीपार्क सर्कल के बीच में लगे विशाल लैंप पोस्ट से आ रही रोशनी शायद यह भ्रम पैदा कर रही थी कि दिन अभी ढला नहीं है।

इंडियन मैना

मशहूर पक्षी विज्ञानी सालिम अली की भांति भार्गव भी एक सच्चे पक्षी प्रेमी बन गए थे। ये पक्षी अपने दैनिक भोजन की तलाश में प्राय: इन खुली जगहों पर उड़ते रहे।

भार्गव का मानना था कि वहां शायद कुछ हजार पक्षी हैं। शायद उनके द्वारा की जा रही आवाज़ को देखते हुए उनकी संख्या पांच हजार हो सकती थी।

वो अभी भी, भ्रम पैदा करने वाली शक्तिशाली आर्टिफिशल लाइट में अभी भी ''दिन'' के लिये अपना गीत गा रही थीं। उनके लिए दिन खत्म नहीं हुआ था।

मैंने सोचा, अपने बैडरूम में लाइट जलाकर सोने की कोशिश करने से शायद बात समझ में आए। ऐसे में ढंग की नींद आना संभव नहीं होगा। शायद, चिड़ियाँ भी इसी तरह की स्थिति से गुज़र रही थीं। वो अपने घोंसलों में अंधेरी रात का थोड़ा एकांत ढूंढ रही थीं।

मुझे अमेरिका तथा पश्चिम के अन्य देशों का वो आंदोलन याद आया, जहां ''डार्क नाइट'' (अंधेरी रात) समूह सामने आ रहे हैं अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि, विश्व भर के बड़े शहरों में रात के समय अत्यधिक रोशनी के कारण ''नाइट स्काय'' का क्षय हो रहा है। ऐसे में असंख्य तारे और ग्रह नज़र ही नहीं आते। यह है नया ''लाइट पोल्यूशन'' जिसने चुपके से पूरे विश्व को ढक लिया है। मुझे याद है कि जब मैं राजाजी नैशनल पार्क गया था तब मैं कितना उत्साहित था। अनगिनत तारों से

(शेष पृष्ठ 7 पर)

कांग्रेस ने शराब घोटाले में केजरीवाल से इस्तीफा मांगा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 4 फरवरी। कांग्रेस ने शनिवार को 10 करोड़ रू. के शराब-घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तथा उनके द्वारा निर्दिष्ट मंत्रियों मनीष सिसोदिया तथा सत्येन्द्र जैन तुरन्त इस्तीफा दें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में ये तीनों ही नेता बेनकाब हो गये हैं। उन्होंने कहा कि पी.एम.एल.ए. (प्रीवेंशन ऑफ मनी-लॉन्डरिंग एक्ट)

- 18-पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने कहा कि, ई.डी. की चार्जशीट में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन का पर्दाफाश हो गया है, तीनों को इस्तीफा दे देना चाहिए।

(शेष पृष्ठ 7 पर)